;

माननीय न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर के समक्ष

कुलबीर सिंह उबेरॉय और एक अन्य, -याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स कुमार इंडस्ट्रीज़- प्रतिवादी

आपराधिक विविध संख्या 54188/2006

7 फ़रवरी 2007परक्राम्य इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881- सेक्शन 138- चेक के डिशोनोर - ट्रायल कोर्ट के बाद प्रारंभिक सबूतों के बाद याचिकाकर्ताओं को बुलाने के लिए प्राइमा फेशी केस रिकॉर्डिंग याचिकाकर्ताओं के मामले को बाहर कर दिया जाता है - एक और चेक को जारी करने के संबंध में - चाहे शिकायत और सम्मन आदेश को छोड़ दिया जाए, जो कि कैश किए जाने के लिए उत्तरदायी है, नहीं, नहीं। एक बार जब कोई शिकायत एक अपराध के कमीशन का खुलासा करती है, तो आरोपों की सत्यता की कार्यवाही में परीक्षण नहीं किया जाना है। आरोपों की सत्यता में भी नहीं जाना है - तिपतिया तौर पर खारिज कर दिया गया - परीक्षण अदालत से पहले याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति को जमा करने के लिए तैयार करने वाले कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन होने से पहले याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति।

आयोजित, कि संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में, यह अदालत आरोपों की सत्यता में नहीं जाना है। एक बार जब कोई शिकायत एक अपराध के कमीशन का खुलासा करती

है, तो आरोपों की सत्यता को संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में परीक्षण नहीं किया जाना है क्योंकि सबूतों की पृष्ठभूमि में परीक्षण किया जाना था जो अभी रिकॉर्ड पर आना बाकी है।

(पैरा 7)

इसके अलावा, कि परक्राम्य उपकरणों की धारा 138 के तहत एक शिकायत में, यदि शिकायत के बारे में मजिस्ट्रेट और प्रारंभिक साक्ष्य के बल पर प्राइमा फेशी के बल पर पाया जाता है कि उसमें किए गए आरोप कानून के प्रावधानों के दायरे में आते हैं। अपराध का आयोग, फिर आवश्यक प्रक्रिया जारी की जानी है। मजिस्ट्रेट को आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के लिए कानून की प्रक्रिया को गति देने के दौरान विस्तृत कारण नहीं देना है। अपराध के आयोग के अवयवों की संतुष्टि शिकायत के कारण से बाहर कर दी गई है, कानून की प्रक्रिया को गति देने के लिए एकमात्र मानदंड है।

(पैरा १०)

इसके अलावा, कि शिकायत और शिकायत के वकील के बयान के बाद ट्रायल कोर्ट ने भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ताओं का समन वांछनीय था। मजिस्ट्रेट की संतुष्टि कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, दर्ज किया गया है। सम्मन के चरण में, अदालत को अभियुक्तों की रक्षा को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी और इसी तरह से इस अदालत को अखाड़े में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, जिसमें शिकायत में किए गए आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी की जानी है।

(पैरा ११)

आशीष चोपड़ा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए

आर.के. छिब्बर, वरिष्ठ अधिवक्ता और सिमरनजीत सिंह चहल, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए

माननीय न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर

(1) याचिकाकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है और प्रावधानों के तहत 25 अक्टूबर, 2005 की शिकायत (अनुलग्नक पी-1) को रद्द करने की प्रार्थना की है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 138 और परिणामी समन आदेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 (अनुलग्नक पी -5) को विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत द्वारा पारित किया गया।

(2) अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रतिवादी द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी। उसमें लगाए गए आरोप यह थे कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 3 मार्च, 2005 को क्रमांक 046173 नाम का एक चेक रुपये की राशि के लिए जारी किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, फरीदाबाद से 2 लाख रुपये निकाले गए। प्रस्तुत करने पर बताया गया कि चेक अनादरित हो गया है। प्रतिवादी द्वारा एक हलफनामे और उसके वकील आशीष गुप्ता के एक बयान के माध्यम से प्रारंभिक साक्ष्य पेश किए

जाने के बाद, अतिरिक्त अदालत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत ने याचिकाकर्ताओं को 25 अक्टूबर, 2005 के आदेश के तहत तलब किया (अनुलग्नक पी-5)

(3) शिकायत और पूर्वोक्त सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण थी क्योंकि 20 सितंबर, 2005 को कानूनी नोटिस जारी करने पर याचिकाकर्ताओं ने एक उत्तर प्रस्तुत किया था। 29 सितम्बर 2005 जो अनुबंध पी-3 के रूप में रिकार्ड में है। इस उत्तर में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि चेक संख्या 046173 दिनांक 3 मार्च, 2005 रुपये की राशि का। मार्च, 2005 में प्रतिवादी-शिकायतकर्ता द्वारा 2 लाख रुपये प्रस्तुत किए गए थे और वह बाउंस हो गए थे, लेकिन सूचना मिलने पर तुरंत याचिकाकर्ताओं ने पिछले चेक के बदले में 23 मार्च, 2005 को दिनांक 00046441 नंबर का एक और चेक जारी किया था। जैसे एक ही बैंक से निकाली गई राशि। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को टेलीफोन पर बातचीत के माध्यम से भी सूचित किया था और पहले चेक को वापस करने के लिए कहा था जो बाउंस हो गया था। चेक वापस करने के बजाय प्रतिवादी ने शिकायत दर्ज करने का सहारा लिया जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था क्योंकि राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका था और हिसाब-किताब का भुगतान हो चुका था। शिकायतकर्ता के खातों का कथित विवरण भी इस याचिका के साथ अनुबंध पी-4/ए के रूप में दायर किया गया था। समन आदेश की भी इस आधार पर आलोचना की गई थी कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया जारी करते समय वही गूढ़ और कोई कारण नहीं बताया गया था, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 29 सितंबर, 2005 को दिए गए नोटिस का जवाब एक हिस्सा था। ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड का.

इसलिए, इसे देखते हुए यह अपर न्यायालय का दायित्व था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के मामले की सुनवाई की। पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य (1) पर भरोसा रखा गया था।

(4) वर्तमान याचिका का प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विरोध किया, जिन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच कई व्यापारिक लेनदेन हुए थे। खातों का निपटान हो जाने और पहले वाले चेक के बदले दूसरा चेक जारी होने की बात से इनकार कर दिया गया। यह कहा गया था कि व्यापार के दौरान और कुछ खातों के निपटान के दौरान अगला चेक जारी किया गया था। 3 मार्च, 2005 के पहले चेक की राशि अभी भी भुगतान नहीं की गई थी, शिकायत पूरी तरह से वैध थी और किसी भी मामले में इस न्यायालय को मामले के तथ्यों पर विचार करने से रोक दिया गया था। आदेश को इस आधार पर उचित ठहराने की मांग की गई थी कि अपराध के घटित होने को स्थापित किया जाना चाहिए जो अदालत के लिए प्रक्रिया जारी करने के लिए पर्याप्त है।

(5) मैंने पार्टियों के वकील को सुना है और रिकॉर्ड देखा है।

(6) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि एक चेक बाउंस हो गया था लेकिन बाद में उक्त चेक के बदले में एक और चेक जारी किया गया था और इसलिए दायित्व समाप्त हो गया। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस तथ्य का जोरदार खंडन किया, जिन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए चेक की फोटो कॉपी का हवाला दिया कि चेक केवल एक बार प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद

एक और चेक जारी किया गया था जो 25 अगस्त, 2005 को वापस कर दिया गया था। भुगतान रोक दिया गया था.

(7) संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में, इस न्यायालय को आरोपों की सत्यता पर ध्यान नहीं देना है। एक बार जब कोई शिकायत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करती है, तो आरोपों की सत्यता का परीक्षण संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका परीक्षण उन सबूतों की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए जो अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं आए हैं।

(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती नागवा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजाल्गी और अन्य में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"जारी करने की प्रक्रिया के चरण में मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से शिकायत में लगाए गए आरोपों या उसके समर्थन में दिए गए सबूतों से चिंतित होता है और उसे केवल प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं। मामले के गुण-दोष की विस्तृत चर्चा करना मजिस्ट्रेट का क्षेत्र नहीं है और न ही उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में इस मामले में जा सकता है जो कि बहुत ही सीमित है।"

X X X X X X X X X

"यह सच है कि इस निर्णय पर पहुंचने में कि क्या कोई प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए, मजिस्ट्रेट शिकायत के चेहरे पर या आरोपों के समर्थन में शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए सबूतों में दिखाई देने वाली अंतर्निहित असंभाव्यताओं पर विचार कर सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने की संभावना और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने की संभावना के बीच एक बहुत ही पतली रेखा तय की जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट को मामले में निस्संदेह विवेकाधिकार दिया गया है और विवेक का प्रयोग उसे न्यायिक रूप से करना होगा। एक बार जब मजिस्ट्रेट अपने विवेक का प्रयोग कर लेता है तो यह उच्च न्यायालय या यहां तक कि उच्चतम न्यायालय का भी काम नहीं है कि वह मजिस्ट्रेट के विवेक को प्रतिस्थापित करे या गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोप हैं या नहीं। यदि शिकायत साबित हो जाती है, तो अंततः आरोपी को दोषी ठहराया जाएगा। ये विचार धारा 202 के तहत जांच के दायरे और दायरे से पूरी तरह से अलग हैं, जो धारा 204 के तहत एक आदेश में परिणत होता है। इस प्रकार निम्नलिखित मामलों में आरोपी के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रक्रिया के आदेश को रद्द किया जा सकता है या अलग रखा जा सकता है:

(1) जहां शिकायत में लगाए गए आरोप या उनके समर्थन में दर्ज किए गए गवाहों के बयान उनके अंकित मूल्य पर आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं या शिकायत किसी अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है जो कि है अभियुक्त के विरुद्ध आरोप;

(2) जहां शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, ताकि कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर न पहुंच सके कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है;

(3) जहां जारी करने की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया गया विवेक विवेकहीन और मनमाना है, या तो बिना किसी सबूत के या ऐसी सामग्री पर आधारित है जो पूरी तरह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य है; और

(4) जहां शिकायत मौलिक कानूनी दोषों से ग्रस्त है,

जैसे, मंजूरी की कमी, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत का अभाव इत्यादि।"

(9) इसके अलावा, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चौ. भजन लाई और अन्य (3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों में, उच्च न्यायालय कला के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 226 या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत। किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए संज्ञेय अपराधों से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। हालाँकि, शक्ति

का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम नस्ल के मामलों में।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया गया हो और पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफ.आई.आर. के साथ संलग्न अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो एक आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है। संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट।

(3) जहां एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि धारा 155(2) के तहत माना गया है। कोड.

(5) जहां एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां कोई विशिष्ट प्रावधान है संहिता या संबंधित अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायतों के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में मुख्य रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

जहां शिकायत में लगाए गए आरोप किसी मामले के पंजीकरण और उस पर जांच को उचित ठहराते हुए एक संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं और ऊपर बताए गए मामलों की किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, असाधारण शक्तियों या अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने, एफ.आई.आर. को रद्द करने की मांग की जाती है। उचित नहीं था"

(10) अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत में यदि मजिस्ट्रेट शिकायत पर गौर करता है और प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया पाता है कि उसमें लगाए गए आरोप

कानून के उपरोक्त प्रावधानों के दायरे में आते हैं जो कमीशन का संकेत देते हैं। अपराध, तो आवश्यक प्रक्रिया जारी करनी होगी। मजिस्ट्रेट को आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के लिए कानून की प्रक्रिया शुरू करते समय विस्तृत कारण नहीं बताना है। शिकायत के अवलोकन से अपराध के घटित होने की सामग्री की संतुष्टि ही कानून की प्रक्रिया को गति देने का एकमात्र मानदंड है। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि नोटिस के जवाब की सामग्री को ट्रायल कोर्ट द्वारा सम्मन का आदेश पारित करते समय निपटाया जाना चाहिए था, तर्कसंगत नहीं है। नोटिस का जवाब याचिकाकर्ताओं, जो आरोपी हैं, का बचाव है और समन के समय इसमें जाना जरूरी नहीं है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने पैरा 28 के विशिष्ट संदर्भ में पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा किया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार देखा था:

' 'आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है, आपराधिक कानून को इस तरह लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपराधिक कानून को अमल में लाने के लिए शिकायतकर्ता को शिकायत में अपने आरोपों के समर्थन में केवल दो गवाह लाने होंगे। अभियुक्त को बुलाने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है। उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की जांच करनी होगी और क्या यह शिकायतकर्ता के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में सफल होने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि अभियुक्त को समन करने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के समय मजिस्ट्रेट मूक दर्शक होता है। मजिस्ट्रेट

को रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए या अन्यथा उत्तर पाने के लिए शिकायतकर्ता और उसके गवाह से खुद भी सवाल पूछ सकते हैं और फिर जांच कर सकते हैं कि क्या कोई अपराध प्रथम दृष्टया सभी या किसी के द्वारा किया गया है। आरोपी का।"

(11) उपरोक्त टिप्पणियों के बारे में बिल्कुल कोई विवाद नहीं है। ट्रायल कोर्ट शिकायत और शिकायतकर्ता के वकील के बयान और हलफनामे पर गौर करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि याचिकाकर्ताओं को बुलाना वांछनीय था। मजिस्ट्रेट की संतुष्टि है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सम्मन के चरण में, अदालत को अभियुक्तों का बचाव पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी और इसी कारण से इस अदालत को उस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया है जहां शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी की जानी है।

(12) ऊपर बताए गए कारणों से, संहिता की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

(13) याचिका खारिज की जाती है।

(14) कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वर्तमान याचिका खारिज करने का वारंट है तो

याचिकाकर्ता रुपये की राशि जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। ट्रायल कोर्ट के समक्ष 2 लाख रुपये और उस स्थिति में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाएगी।

(15) परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य के विशेष संदर्भ में कि पार्टियों के पास व्यापारिक सौदे हैं, यह उचित होगा यदि याचिकाकर्ताओं को रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाए। तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष 2 लाख रु. ऐसी राशि जमा करने की स्थिति में, याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति को निम्नलिखित शर्तों में हलफनामा दाखिल करने की शर्त पर छूट दी जाएगी:

(i) जब भी निर्देश दिया जाए, ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का वचन दूंगा;

(ii) उपक्रम करना यदि उनकी अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी;

(iii) पहचान के संबंध में कोई विवाद न उठाने का वचन देना;

(iv) ऐसी अन्य शर्तों का पालन करने का वचन देगा, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जा सकती हैं।

वकील के माध्यम से उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है।

(16) यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता हलफनामे और ऐसी शर्तों से बंधे होंगे, जिन्हें ट्रायल कोर्ट उचित समझे। यदि याचिकाकर्ता हलफनामे के नियमों और शर्तों, या ऐसे अन्य नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए हैं, तो ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा